

बिहार की कोसी-मेची लकि परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ

चर्चा में क्यों?

25 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की अति महत्वपूर्ण कोसी-मेची लकि परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना का डीपीआर बनाने के लिये जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- कोसी-मेची लकि परियोजना के पूरा होने पर राज्य के सीमांचल के चार जिलों में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में संचाई सुविधा और बाढ़ से राहत मिलेगी। इनमें पूर्णिया, कटहिर, कशिनगंज और अररिया जिला शामिल हैं।
- इस परियोजना से अररिया जिले में करीब 69 हजार हेक्टेयर, पूर्णिया जिले में करीब 69 हजार हेक्टेयर, कशिनगंज जिले में 39 हजार हेक्टेयर और कटहिर जिले में 35 हजार हेक्टेयर जमीन की संचाई होगी।
- कोसी-मेची लकि परियोजना से अररिया जिले के अंतर्गत फारबिसगंज, कुरसाकाटा, सकिटी, पलासी, जोकीहाट एवं अररिया प्रखंड को लाभ होगा। वहीं, कशिनगंज जिले के अंतर्गत टेढ़ागाछ, दधिलबैंक, बहादुरगंज एवं कोचाधामन प्रखंड को लाभ होगा।
- इसके अलावा पूर्णिया जिले के अंतर्गत बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखंड तथा कटहिर जिले के अंतर्गत कदवा, डंडखोड़ा, प्राणपुर, मनहारी एवं अमदाबाद प्रखंड लाभान्वित होंगे।
- वदिति है कि कोसी-मेची लकि परियोजना का काम शुरू करने के लिये पहले ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मई 2022 में ही राज्य सरकार ने डीपीआर गठन, सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिये करीब दो करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासनिक और खर्च की स्वीकृति दी थी।
- राज्य सरकार द्वारा 90 फीसदी केंद्रांश की हो रही मांग तथा केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, इसके लिये केंद्रांश 60 फीसदी और राज्यांश 40 फीसदी के रूप में बजटीय प्रावधान की मंजूरी दी गई है।
- हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कोसी-मेची लकि परियोजना के लिये भी मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लकि परियोजना की तरह पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान की मांग जारी है।
- इस परियोजना के अंतर्गत कुल लगभग 1397 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 632 हेक्टेयर भूमि पूर्व से अधिगृहीत है, जबकि 765 हेक्टेयर नजि भूमि अधिग्रहण किया जाना है।